



परमाणु क्षति के लिये नागरकि दायतित्व अधनियम 2010

प्रलिमिस के लिये:

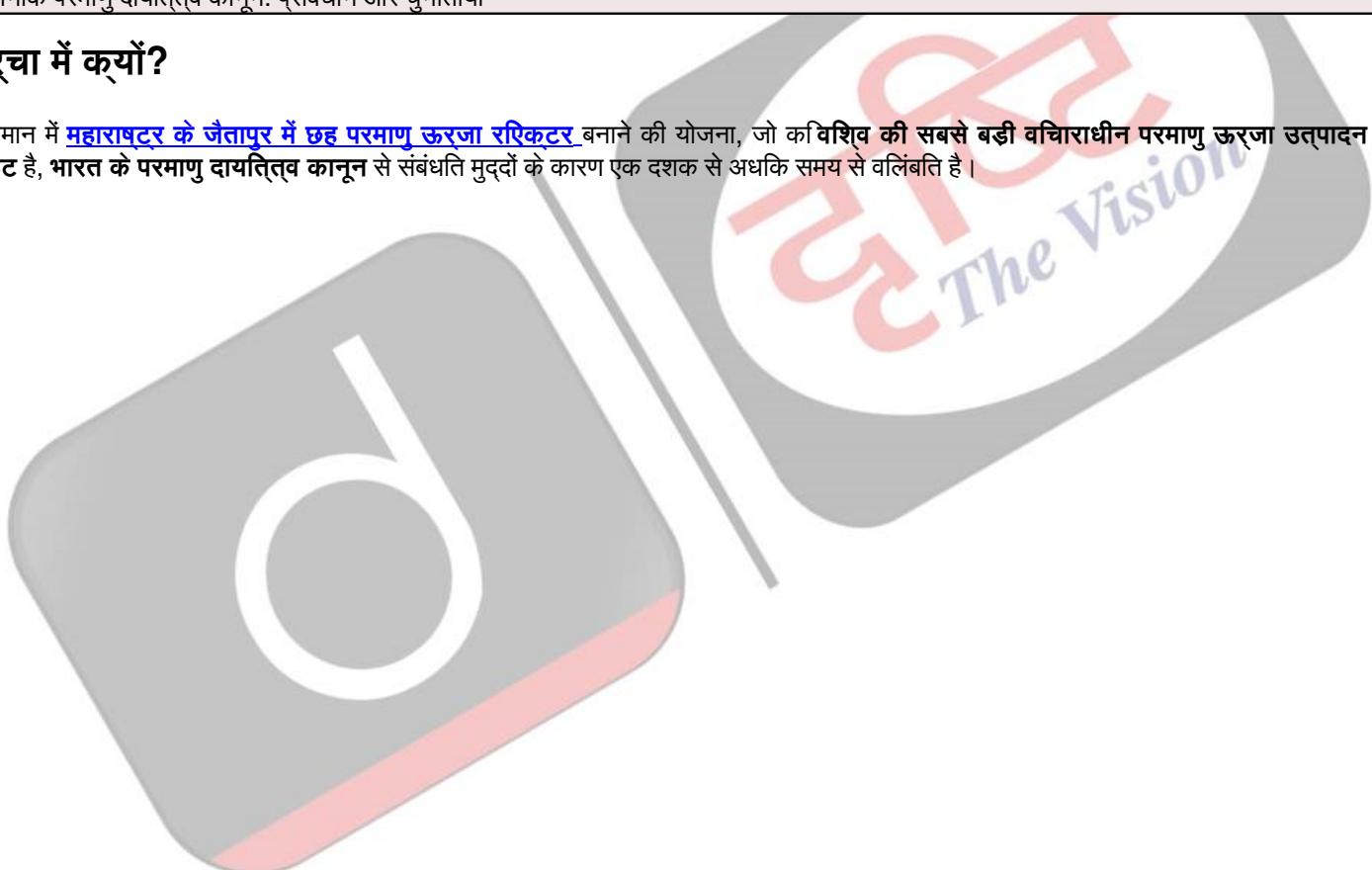
पूरक मुआवजे पर अभसिमय (Convention on Supplementary Compensation- CSC), परमाणु क्षति के लिये नागरकि दायतित्व अधनियम, 2010, [न्युक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया \(NPCIL\)](#)

मेन्स के लिये:

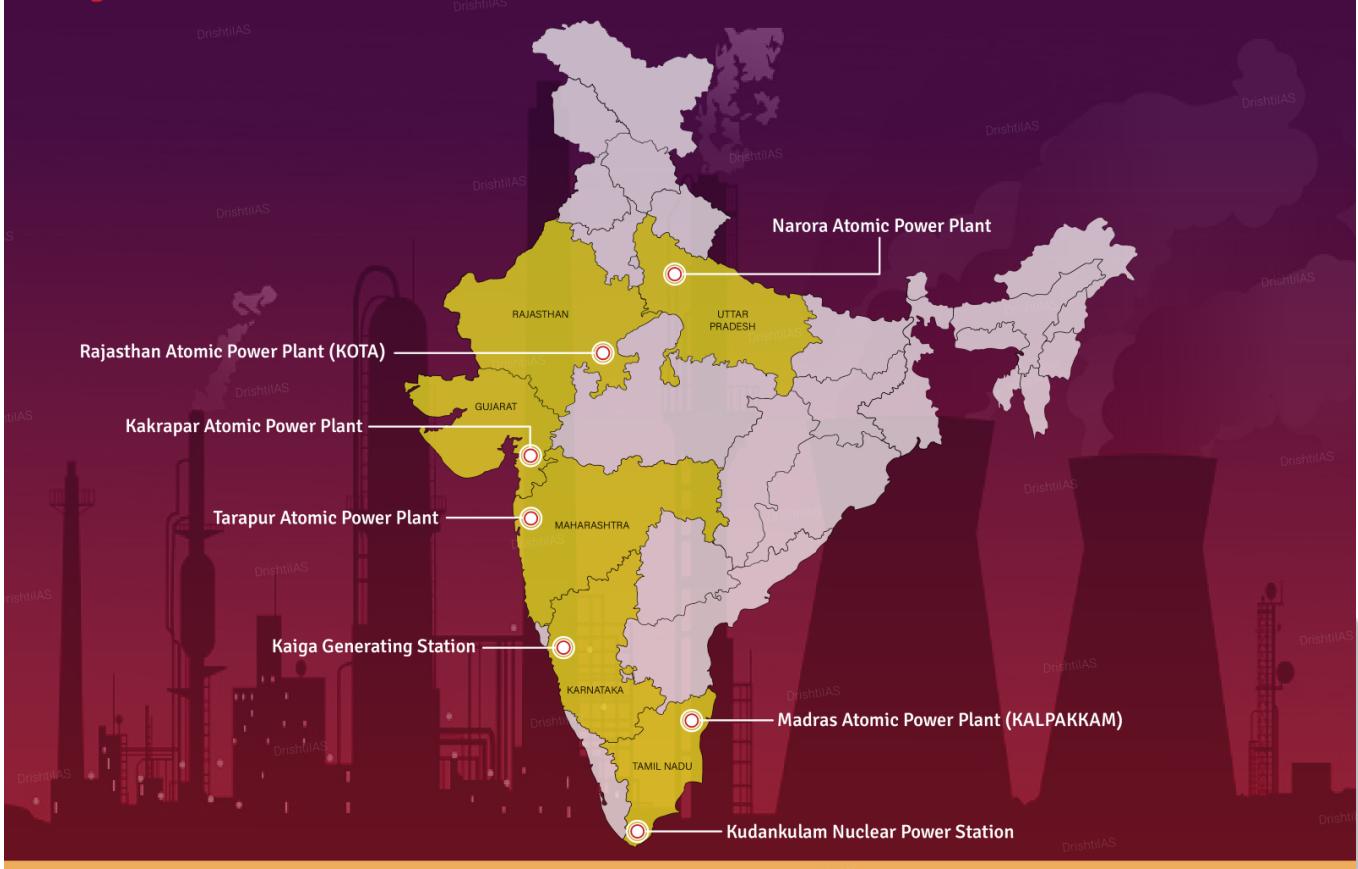
असैनकि परमाणु दायतित्व कानून: परावधान और चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

वर्तमान में [महाराष्ट्र के जैतापुर में छह परमाणु ऊर्जा रएक्टर](#) बनाने की योजना, जो कविशिव की सबसे बड़ी विचाराधीन परमाणु ऊर्जा उत्पादन साइट है, भारत के परमाणु दायतित्व कानून से संबंधित मुद्दों के कारण एक दशक से अधिक समय से वलिंबति है।



Operational Nuclear Power Plants in India



FACTS

- Presently, India has 22 nuclear power reactors operating in 6 states, with an installed capacity of 6780 MegaWatt electric (MWe).
- Activities concerning the establishment and utilization of nuclear facilities and use of radioactive sources are carried out in India in accordance with the **Atomic Energy Act, 1962**.
- Atomic Energy Regulatory Board (AERB) regulates nuclear & radiation facilities and activities.
- Newest & Largest Nuclear Power Plant:** Kudankulam Power Plant, Tamil Nadu.
- First & Oldest Nuclear Power Plant:** Tarapur Power Plant, Maharashtra.

असैन्य परमाणु दायतित्व पर कानून:

■ परचियः

- असैन्य परमाणु दायतित्व पर कानून यह सुनिश्चिति करता है कि परमाणु घटना या आपदा के कारण पीड़ितों को हुई क्षतिके लिये मुआवजा उपलब्ध कराया जाए और यह भी निरिधारित करता है कि उस क्षतिके लिये कौन उत्तरदायी होगा।

■ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनः

- परमाणु क्षतिके लिये नागरकि दायतित्व पर कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरणों के लिये डिपिंजिटिरी के रूप में कार्य करता है। इनमें परमाणु क्षतिके लिये नागरकि दायतित्व पर विना अभिसमय और परमाणु क्षतिके लिये पूरक मुआवजे पर अभिसमय शामलि हैं।
- न्यूनतम राष्ट्रीय मुआवजा राशि सुनिश्चिति करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में पूरक मुआवजा पर व्यापक अभिसमय (CSC) को अपनाया गया था।

- भारत ने वर्ष 2016 में CSC की पुष्टिकी है।

■ परमाणु क्षतिके लिये नागरकि दायतित्व अधिनियम, 2010 (India's Civil Liability for Nuclear Damage Act- CLNDA):

◦ उद्देश्यः

- भारत ने वर्ष 2010 में परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों हेतु एक त्वरित मुआवजा तंत्र स्थापित करने के लिये CLNDA को अधिनियमित किया था।

० संचालकों पर देयता:

- CLNDA के अनुसार, परमाणु संयंत्र के संचालक सख्त और बनि कसी गलती के दायतित्व के अधीन हैं, जिसका अर्थ है कि वह कसी भी लापरवाही एवं नुकसान हेतु उत्तरदायी है।
- यह नरिदिष्ट करता है कि दुर्घटना के कारण हुए नुकसान के मामले में संचालकों को 1,500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना होगा।

० इसके लिये संचालकों को बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से देयता को कवर करने की भी आवश्यकता होती है।

० सरकार की भूमिका:

- CLNDA अपेक्षा करता है कि यदि नुकसान का दावा 1,500 करोड़ रुपए से अधिक है तो सरकार हस्तक्षेप करेगी।
- इसने सरकारी देयता राशि को रुपए में 300 मलियन विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights- SDR) के बराबर तक सीमित कर दिया है।
- आपूरतकिरत्ता देयता उपबंध: यह ध्यान देने की बात है कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हेतु दोषपूरण पुरजे काफी हद तक जमिमेदार थे, सरकार ने CLNDA में संचालकों की देयता के अलावा आपूरतकिरत्ता देयता को शामिल करने के लिये CSC के प्रावधानों से परे जाकर देयता सुनिश्चित की है।
 - इस प्रावधान के तहत यदि कोई परमाणु घटना दोषपूरण उपकरण अथवा सामग्री, खराब सेवाओं या आपूरतकिरत्ता कर्मचारियों के आचरण के परिणामस्वरूप होती है, तो परमाणु संयंत्र का संचालक आपूरतकिरत्ता से संपर्क कर उचित मदद की मांग कर सकता है।

नोट:

- CSC के अनुसार, "केवल" दो परस्थितियों में कसी राष्ट्र का राष्ट्रिय कानून एक आपूरतकिरत्ता को उत्तरदायी ठहराने के लिये संचालक को "मदद का अधिकार" प्रदान कर सकता है।
- अगर यह अनुबंध में विशेष रूप से वरणति है।
- अगर परमाणु घटना "नुकसान पहुँचाने के इरादे से किया गया कसी कार्य अथवा चूक के परिणामस्वरूप होती है।"

परमाणु सौदों में आपूरतकिरत्ता दायतित्व खंड:

- विदेशी और घरेलू आपूरतकिरत्ता ऑं के लिये बाधक: यह देखते हुए कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास आपूरतकिरत्ता ऑं से नुकसान की मांग की अनुमति देने वाला कानून है, परमाणु उपकरणों के घरेलू और विदेशी दोनों नरिमाता भारत के साथ परमाणु समझौते को लागू करने के लिये अनियुक्त रहे हैं।
- आपूरतकिरत्ता ऑं के लिये अधिक जोखिमपूरण: आपूरतकिरत्ता ऑं ने CLNDA के तहत संभावति रूप से असीमित देयता के संपर्क में आने के बारे में चिंता जताई है कि क्योंकि मुआवजे की राशि कानून के तहत तय नहीं है क्योंकि यह ऑपरेटर के लिये तय की गई है।
- चूंकि मुआवजे की राशि आपूरतकिरत्ता ऑं के लिये कानून दवारा उस प्रकार निर्धारित नहीं है जैसा कि संचालकों के लिये निर्धारित है, आपूरतकिरत्ता ऑं ने CLNDA के तहत संभावति रूप से असीमित दायतित्वों को लेकर चिंता व्यक्त की है।
 - इसके अतरिक्त उन्होंने इस अस्पष्टता को भी उजागर किया है कि किष्टके मामले में मुआवजे हेतु कठिनी राशि को पृथक रखना है।
- स्पष्टता की कमी में अन्य कानून शामिल हैं: 'परमाणु क्षति' के प्रकारों पर एक व्यापक परभिष्ठि के अभाव में अधिनियम संभावति रूप से अन्य नागरिक कानूनों के माध्यम से ऑपरेटर और आपूरतकिरत्ता ऑं के खलिक नागरिक देयता के दावों को लाने की अनुमति देता है।
- आपराधिक देयता को आकर्षित करता है: अधिनियम कसी व्यक्तिको इस अधिनियम के अतरिक्त कसी अन्य कानून के तहत ऑपरेटर के खलिक कार्यवाही करने से नहीं रोकता है। यह जहाँ भी लागू हो, ऑपरेटर और आपूरतकिरत्ता के खलिक आपराधिक देयता का अनुसरण करने की अनुमति देता है।

CLNDA के साथ अन्य समस्याएँ :

- मुआवजे पर मौद्रक सीमा: अधिनियम एक निश्चित मौद्रक सीमा तक देयता तय करता है (ऑपरेटरों के लिये 1,500 करोड़ रुपए और सरकार के लिये विशेष आहरण अधिकार के तहत 300 मलियन रुपए)। इस तरह की सीमा के साथ सबसे बड़ी समस्या ऐसी स्थितियों में पैदा होती है जब नुकसान सीमा से अधिक हो जाता है।
 - अधिनियम स्पष्ट रूप से सीमा से अधिक नुकसान की लागत के संबंध में कोई प्रावधान प्रदान नहीं करता है।
- करदाताओं पर बोझ: भारत में ये संयंत्र सरकार के सवामित्व वाले हैं और NPCIL के माध्यम से संचालित होते हैं। अंततः ऐसी आपदाओं की क्षतिपूरता आम करदाताओं दवारा वहन की जाएगी।
- अतरिक्त लागतों की उपेक्षा: चेर्नोबल जैसी विगत घटनाओं से ज्ञात हुआ है कि परमाणु घटना के लिये दोषी पक्ष को परमाणु अपशिष्ट की सफाई एवं सुरक्षित निपटान जैसी अतरिक्त लागतें वहन करनी चाहिए, जो महँगी हैं तथा इसमें अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
 - हालाँकि अधिनियम इन अतरिक्त लागतों के लिये कोई प्रावधान नहीं करता है।

- कोई विदेशी अधिकार क्षेत्र नहीं: भारत कई विदेशी आपूर्तकिरताओं से आपूर्ति करता है जो भारतीय कानून के अनुसार विदेशी संस्थाएँ हैं। भारतीय मुआवजे की मांग के लिये विदेशी न्यायालय में नहीं जा सकते।

आगे की राह

- विदेशी आपूर्तकिरता से मुआवजा मांगे जाने की स्थिति में विदेशी न्यायालयों तक पहुँच प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के प्रावधान किये जाने चाहये। अंतर्राष्ट्रीय समझौते या एक मजबूत विवाद समाधान तंत्र बनाया जा सकता है।
- आपूर्तकिरताओं को विश्वास में लेने हेतु उनकी देनदारी की सीमा भी सुनिश्चित होनी चाहये तथा बीमा राशि की भी अधिकतम सीमा निश्चित होनी चाहये।
- अस्पष्टता के समाधान हेतु कानून में संशोधन किया जाना चाहये और आपराधिक दायतित्व के प्रावधानों को आसान बनाया जाना चाहये या आपराधिक कारबाही के दायरे को स्पष्ट किया जाना चाहये।
- वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र का अन्वेषण किया जाना चाहये, जैसे किंविता या एक समर्पित निधि जो यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक भार पूरी तरह से करदाताओं पर नहीं है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में समय-समय पर परमाणु सुरक्षा शिविर सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं।
2. विंडिंगनीय सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का एक अंग है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: d

प्रश्न. भारत में क्यों कुछ परमाणु रिक्टर "आई.ए.ई.ए सुरक्षा उपायों" के अधीन रखे जाते हैं, जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020)

- (a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का।
- (b) कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्तिका।
- (c) कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा।
- (d) कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य नजीबी स्वामित्व वाले।

उत्तर: b

प्रश्न:

प्रश्न. बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताओं को देखते हुए क्या भारत को अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करते रहना चाहये? परमाणु ऊर्जा से जुड़े तथ्यों और आशंकाओं पर चर्चा कीजिये। (2018)

प्रश्न. भारत में परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वृद्धि एवं विकास का विवरण दीजिये। भारत में फास्ट ब्रीडर रिक्टर कार्यक्रम के क्या लाभ हैं? (2017)

स्रोत: द हंड्री

